BCCI BULLETIN

Vol. 52 | FEBRUARY 2021 | No.2

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर ने कहा, कुल मिलाकर बजट संतुलित

चैम्बर में केन्द्रीय बजट 2021-22 का सीधा प्रसारण देखते चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल, श्री राजेश खेतान, श्री सुनील सराफ एवं अन्य।

केन्द्रीय आम बजट को लेकर उद्योग एवं कारोबार जगत को ढेरों उम्मीदें थी। व्यापारिक संगठनों ने कहा कि इस बजट को पूरी तरह बुरा नहीं कहा जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में यह संतुलित बजट है। लेकिन, बिहार के नजरिये से इस बजट में कुछ सौगात नहीं है।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा कि कोरोना महामारी और राजस्व संग्रहण में परेशानी के बावजूद केंद्र सरकार ने संतुलित बजट पेश किया। केन्द्रीय बजट को लेकर चैम्बर में लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गयी थी। इस अवसर पर काफी संख्या में पदाधिकारी एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

"इस बार के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर व रिफार्म पर फोकस करते हुए अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का प्रयास किया है। भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोविड -19 महामारी के कारण बजट पपेरलेस पेश किया गया है। अगर राष्ट्रीय स्तर पर इसको देखा जाये तो महामारी के कारण आई आर्थिक मंदी से उबरने पर विशेष जोर दिया गया है।"

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष
बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज

"बजट को लेकर मध्यम वर्ग में काफी अपेक्षाएं थी। सरकार ने आयकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया है न ही कोई बड़ी छूट मध्यम वर्ग

चैम्बर में केन्द्रीय बजट 2021-22 का सीधा प्रसारण देखते चैम्बर के पदाधिकारीगण एवं सदस्यगण।

के लिए दिखाई दी है। स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सरकार में बड़ी घोषणाएं की है जिसका लाभ समाज के हर तबके को मिलेगा।"

– राजेश खेतान, चार्टर्ड एकाउंटेंट

"वित्त मंत्री ने अपने बजट प्रस्तावों में सोने और चांदी पर आयात शुल्क में पांच फीसदी की कटौती की है। फिलहाल सोने और चांदी पर 12.5 फीसदी आयात शुल्क चुकाना पड़ता है। इस तरह से अब सोने और चांदी पर सिर्फ 7.5 फीसदी इम्पोर्ट ड्यूटी चुकानी होगी।"

– विनोद कुमार, अध्यक्ष, पाटलिपुत्रा सर्राफा संघ

(साभार : प्रभात खबर, 2.2.2021)

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं

केन्द्रीय बजट 2021–22 एक फरवरी, 2021 को माननीया वित मंत्री ने प्रस्तुत किया। **कोरोना महामारी और राजस्व संग्रहण में परेशानी के बावजूद केन्द्र सरकार ने संतुलित बजट पेश किया।** भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस बजट में आर्थिक मंदी से उबारने पर विशेष जोर दिया गया है। **बिहार के स्तर पर देखा जाय तो बिहार की आम जनता के साथ–साथ राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों को बजट से उम्मीदों की जगह निराशा हाथ लगी है।** बजट की घोषणाओं से किसानों और छोटे व मध्यमवर्गीय लोग अवश्य लाभान्वित होंगे।

बजट से पता चलता है कि छोटे कारोबारियों को अब तीन साल तक के लेन–देन का ही रिकार्ड रखना होगा। अभी कारोबारियों को छह साल का रिकार्ड रखने का प्रावधान है। केन्द्रीय वित मंत्री द्वारा बजट में समय सीमा को घटा दिया गया है। इससे कारोबारियों को काफी राहत मिलने की संभावना है।

यह हर्ष की बात है कि माननीय केन्द्रीय वित मंत्री ने आम बजट 2021–22 में आगामी तीन वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। **इसके लिए चैम्बर की ओर से माननीय वित मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, माननीय केन्द्रीय टेक्सटाइल्स मंत्री श्रीमती स्मृति इरानी से एक टेक्सटाइल पार्क बिहार में भी स्थापित करने का आग्रह किया गया है। साथ ही बिहार के सभी माननीय सांसदों से भी आग्रह किया गया है कि इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध करें।**

22 फरवरी, 2021 को माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने बिहार बजट 2021–22 पेश किया। **कोरोना काल में भी बिहार बजट का आकार में 3 प्रतिशत की वृद्धि स्वागत योग्य है।** बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और महिलाओं पर विशेष ध्यान देना स्वागत योग्य है। राज्य में तीन नये मेडिकल कॉलेज खोलना, छात्रों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस, महिलाओं के लिए विशेष उद्यम योजना आदि घोषणाएं स्वागत योग्य हैं। राज्य में अधिक से अधिक उद्योग लगे इसके लिए एक रोड मैप बनाने की आवश्यकता है ।

दिनांक 5 फरवरी, 2021 को Aakhya India की ओर से **Webinar on E-Commerce Opportunity for MSMEs in Bihar** का आयोजन किया गया था जिसमें मैं as a panalist शामिल हुआ ।

दिनांक 6 फरवरी, 2021 को चैम्बर द्वारा Institute of Company Secretaries of India (ICSI) पटना चैप्टर के सहयोग से **''पोस्ट बजट टॉक''** का आयोजन हुआ जिसमें **श्री सुशील कुमार मोदी माननीय सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार ने** आम बजट 2021–22 की बारीकियों एवं विशेषताओं की विस्तृत जानकारी दी।

दिनांक 6 फरवरी, 2021 को ही बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से **आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वरोजगार हेतु 11 ठेला प्रदान किया गया ताकि वे सब्जी, फल एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री कर अपना एवं अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सके।** इस कार्य के समय–समय पर आकलन एवं संचालन का जिम्मा रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा को दिया गया है।

बिहार मंत्रीमंडल के विस्तार के बाद नये मंत्री मंडल के सभी माननीय मंत्रियों को मैं अपनी तरफ से एवं बिहार के समस्त व्यवसायियों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ।

चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल मेरे नेतृत्व में दिनांक 10 फरवरी, 2021 को माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन से मिला एवं उन्हें बधाई दी। इसके अतिरिक्त बिहार के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास पर चैम्बर की ओर से हर सम्भव सहयोग का आश्वासन दिया गया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, वरीय सदस्य श्री रामाशंकर प्रसाद एवं श्री आलोक पोद्दार शामिल थे।

प्रेस इंफॉर्मेशन ब्युरो एवं रिजनल आउटरिच ब्युरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से दिनांक 11 फरवरी, 2021 को केन्द्रीय बजट 2021–22 पर एक **Webinar** आयोजित हुई जिसमें मैं बतौर एक Panalist सम्मिलित हुआ।

दिनांक 24 फरवरी, 2021 को चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन0 के0 ठाकुर के नेतृत्व में माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन से मिलकर उन्हें बधाई दी एवं उनका अभिनन्दन किया। प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, वरीय सदस्य श्री ए0 के0 पी0 सिन्हा, श्री आलोक पोद्दार एवं श्री राजेश माखरिया सम्मिलित थे ।

27 फरवरी, 2021 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा मुम्बई के मिठाई, नमकीन एवं स्नैक्स निर्माताओं की शीर्ष संस्था फेडेरेशन ऑफ स्वीट्स एण्ड नमकीम मैन्यूफैकचरर्स के साथ एक बैठक आयोजित हुई।

सादर,

आपका

पी0 के0 अग्रवाल

सात में एक टेक्सटाइल पार्क बिहार को भी मिले : पी. के. अग्रवाल

आम बजट में सात टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा हुई है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केन्द्रीय टेक्सटाइल मंत्री स्मृति ईरानी से आग्रह किया गया है कि इनमें से एक पार्क बिहार में भी स्थापित किया जाए।

चैम्बर के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा है कि अगले तीन वर्षों में सात टेक्सटाइल पार्क लगाने की घोषणा आम बजट में की गई है। यह सराहनीय कदम है। बिहार औद्योगिक रूप से पिछड़ा राज्य है। जनसंख्या के मामले में यह देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। कोरोना काल में दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक बिहार आए हैं। इसमें टेक्सटाइल से जुड़े श्रमिक भी शामिल हैं, जो बेरोजगार हैं। अगर बिहार को एक टेक्सटाइल पार्क मिल जाता है तो इससे श्रमिकों की बेरोजगारी दूर होगी। साथ ही राज्य का आर्थिक विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि चैम्बर की ओर से केन्द्रीय वित्त मंत्री और केन्द्रीय टेक्सटाइल मंत्री से इसके लिए आग्रह किया गया है।

साथ ही बिहार के सभी राज्यसभा और लोकसभा सांसदों से भी आग्रह किया गया है कि वे इसके लिए भारत सरकार से अनुरोध करें।

(साभार : दैनिक जागरण, 10.2.2021)

चैम्बर ने वित्त मंत्री को दिए बजट को लेकर सुझाव

बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता करते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, विभागीय अधिकारीगण एवं चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

ई-वे बिल की वैधता की सीमा बढ़ाने और जीएसटीआर-3बी में सुधार समेत की गयी हैं कई मांगें

साल 2021-2022 के बजट के लिए बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने दिनांक 3.2.2021 को वित्त मंत्री को राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के कई सुझाव दिए हैं। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बताया कि बजट पूर्व बैठक में करारोपण से संबंधित आवश्यक सुधार के लिए सुझाव दिए गए।

- इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के नियम में बदलाव किया जाये।
- ईवे बिल की वैधता की सीमा को बढ़ाया जाये क्योंकि पहले 100 किलोमीटर की दूरी पर एक दिन का समय दिया जाता था उसे बढ़ाकर 200 किलोमीटर तक के लिए भी एक ही दिन किया गया है।
- व्यवसायियों के पंजीयन को बर्खास्त करने का जो अधिकार विभाग के अधिकारियों को दिया गया है उसे वापस लिया जाये।
- जीएसटीआर-3बी में सुधार किया जाये।
- जीएसटीआर-1 के लिए लागू विलंब शुल्क को माफ किया जाये।
- वैट में फार्म-सी/एफ में सुधार का अवसर दिया जाये।
- भूमि पर क्रेता को आनुपातिक हिस्सेदारी का अधिकार रखते हुए भूमि की लागत को मूल्यांकन रकम में अलग से नहीं जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वित्त वर्षों में सर्किल रेट में कई-कई बार बढ़ोतरी होने के कारण ऐसा देखा जा रहा है कि अधिकांशत: किसी भी अचल निर्मित संपत्ति के निबंधन के लिए मूल्याकंन रकम उसके वास्तविक क्रय रकम से अधिक हो जाती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव क्रेता को आयकर नियमों के तहत भी झेलना पड़ता है।
- रोड टैक्स पड़ोसी राज्यों के समान रखा जाये क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि क्रेता महंगे वाहन को अन्य पड़ोसी राज्यों से खरीद ले रहे हैं जिससे राज्य को बिक्री पर मिलने वाले टैक्स की रकम अन्य राज्यों को चली जाती है। साथ ही जब वो वाहन हमारे ही राज्य में अवस्थित सर्विस केन्द्र पर सर्विस सुविधा लेता है तो उस पर मिलने वाली जीएसटी की राशि हमारे राज्य को प्राप्त नहीं होती है क्योंकि वाहन दूसरे राज्य के पते पर निर्बंधित होता है।
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राज्य की औद्योकि इकाइयों से संबंधित यदि कोई नया प्रावधान लाया जाता है तो उसके कार्यान्वयन के पूर्व उद्यमियों को जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर विस्तृत जानकारी दी जानी चाहिए।
- यदि कोई उद्योग द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुज्ञप्ति के लिए निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन किया जाता है और किसी कारणवश वह आवेदन रद्द हो जाता है तो पुन: आवेदन करने पर पर्षद की ओर से फिर से निर्धारित शुल्क जमा कराने को कहा जाता है, जबकि उद्यमी की ओर से पहले ही आवेदन शुल्क जमा किया जा चुका है। एक ही कार्य के लिए दो बार शुल्क की जमा करना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।
- बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से राज्य के उद्योगों से संबंधित जो विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है वह धमकी भरा होता है जिससे राज्य के उद्यमियों में भय व्याप्त हो जाता है और हतोत्साहित होते हैं, अत: इस प्रकार के विज्ञापन पर अंकुश लाया जाना चाहिए।
- ध्वनि प्रदूषण पर पटना उच्च न्यायालय ने भी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है परन्तु अभी भी ऐसा देखा या है कि प्रतिबंधित अवधि जो रात्रि 10 से सुबह 6 बजे तक की है, इसमें भी लाउड स्पीकर बजाया जाता है। अत: इसका सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही पटना के विभिन्न भागों में अवस्थित होटलों और मैरेज हॉल के बाहर सख्ती से अनुपालन का बोर्ड लाया जाना चाहिए तथा उक्त बोर्ड में इसके वायलेशन पर उसकी सूचना देने के लिए संबंधित पदाधिकारियों का मोबाइल नम्बर भी दिया जाना चाहिए। शादी-विवाह में देर रात को बजने वाले डीजे, बैंड आदि पर सख्ती से रोक लगाए जाने की आवश्यकता है।

(साभार : राष्ट्रीय सहाय, 4.2.2021)

"E-Commerce Opportunity for MSMEs in Bihar" पर वेबिनार आयोजित

Akhya India की ओर से 5 फरवरी 2021 को **"E-Commerce Opportunity for MSMEs in Bihar"** पर वेबिनार आयोजित हुई। वेबिनार में माननीया उप-मुख्यमंत्री-सह-उद्योग मंत्री श्रीमती रेणु देवी, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री बृजेश मेहरोत्रा एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने भाग लिया।

उक्त अवसर पर चैम्बर अध्यक्ष ने सभी E-Commerce कंपनियो से अनुरोध किया कि बिहार में उत्पादित सामग्रियों को देश-विदेश में वृहत रूप से प्रचारित करें।

"E-Commerce opportunity for MSME in Bihar" पर वेबिनार में सम्मिलित माननीया उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, उद्योग विभाग के अपर मुख्यसचिव श्री बृजेश मेहरोत्रा, चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल एवं अन्य वक्तागण

विस्तार के बाद बिहार का मंत्रिमंडल

राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ ही राज्य मंत्रिमंडल में शामिल सभी 31 मंत्रियों के बीच विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर मुहर लगाते हुए राज्यपाल फागू चौहान ने दिनांक 9 फरवरी 2021 की शाम मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन कर दिया।

- **मुख्यमंत्री नीतीश कुमार** : सामान्य प्रशासन, गृह, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन एवं ऐसे सभी विभाग जो किसी को आवटित नहीं हैं रहेंगे।
- **उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद** : वित्त, वाणिज्य कर एवं नगर विकास एवं आवास विभाग
- **उप मुख्यमंत्री रेणु देवी** : आपदा प्रबंधन एवं पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
- **विजय कुमार चौधरी** : शिक्षा एवं संसदीय कार्य विभाग
- **बिजेन्द्र प्रसाद यादव** : ऊर्जा तथा योजना एवं विकास विभाग
- **अशोक चौधरी** : भवन निर्माण
- **शीला कुमारी** : परिवहन विभाग
- **संतोष कुमार सुमन** : लघु जल संसाधन एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण
- **मुकेश सहनी** : पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
- **मंगल पाण्डे** : स्वास्थ्य विभाग
- **अमरेन्द्र प्रताप सिंह** : कृषि विभाग
- **डॉ. रामप्रीत पासवान** : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
- **जीवेश कुमार** : श्रम संसाधन तथा सूचना प्रावैधिकी विभाग
- **रामसूरत कुमार** : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
- **सैय्यद शाहनवाज हुसैन** : उद्योग
- **श्रवण कुमार** : ग्रामीण विकास
- **मदन सहनी** : समाज कल्याण
- **प्रमोद कुमार** : गन्ना उद्योग एवं विधि
- **संजय कुमार झा** : जल संसाधन तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
- **लेसी सिंह** : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
- **सम्राट चौधरी** : पंचायत्ती राज
- **नीरज कुमार सिंह** : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- **सुबाष सिंह** : सहकारिता विभाग
- **नितिन नवीन** : पथ निर्माण विभाण
- **सुमित कुमार सिंह** : विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
- **सुनील कुमार** : मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
- **नारायण प्रसाद** : पर्यटन विभाग
- **जयंत राज** : ग्रामीण कार्य विभाग
- **आलोक रंजन** : कला संस्कृति एवं युवा विभाग
- **मो. जमा खान** : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
- **जनक राम** : खान एवं भूतत्व

(साभार : हिन्दुस्तान, 10.2.2021)

चैम्बर में "पोस्ट बजट सेमिनार–सह–टॉक" आयोजित

पोस्ट बजट सेमिनार में स्वागत संबोधन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल।
उनकी बाँयीं ओर क्रमशः रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज श्री हिमांशु शेखर एवं माननीय सांसद राज्यसभा एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 6 फरवरी 2021 को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज (बीसीसीआई) एवं इंस्टीच्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (ICSI) पटना चैप्टर के संयुक्त तत्वावधान में **'पोस्ट बजट सेमिनार-सह-टॉक'** का आयोजन किया गया।

माननीय सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री. पी. के. अग्रवाल

माननीय सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी को अंगवस्त्र से सम्मनित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में आईसीएआई पटना चैप्टर की चेयरपर्सन सीएस पूजा कसेरा।

पोस्ट बजट सेमिनार को संबोधित करते माननीय सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी। उनकी दाँयी ओर क्रमशः रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज श्री हिमांशु शेखर एवं चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। बाँयी और आईसीएसआई पटना चैप्टर की चेयरपर्सन सीएस पूजा कसेरा।

कार्यक्रम में माननीय सांसद (राज्य सभा) एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री सुशील कुमार मोदी बतौर मुख्य अतिथि तथा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज श्री हिमांशु शेखर उपस्थित थे।

अपने स्वागत संबोधन में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि आज के कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य केन्द्रीय बजट 2021-2022 की बारीकियों के बारे में सदस्यों को अवगत कराना था।

श्री सुशील कुमार मोदी ने केन्द्रीय बजट का उल्लेख करते हुए कहा कि आम लोगों के लिए यह संतोषप्रद है कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में वृहत पैमाने पर प्राप्त होने वाले राजस्व में नुकसान के बावजूद राज्य के उद्योग, व्यवसाय एवं आम लोगों को आर्थिक मदद पहुँचाया गया है। इस बार के बजट में चार मुख्य विन्दुओं जैसे – स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर (कैपिटल एक्सपेंडीचर), वित्तीय सुधार एवं एसेट रिकंस्ट्रक्शन पर केन्द्रित है। श्री मोदी ने कहा की वित्तीय सुधार के लिए डेवलपमेंट फिनांशियल इंस्टीच्यूट के गठन का प्रस्ताव किया गया है, ताकि सरकार की ओर से बैंकों के एनपीए में सुधार किया जा सके। डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से राजस्व को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा।

पूर्व उप मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य प्रक्षेत्र पर 2020-21 की तुलना में 137 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2021-22 में 2.23 लाख करोड़ रूपये खर्च करेगी, जबकि जल व स्वच्छता पर बजट में 346 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है।

कोविड वैक्सीनेशन पर 35 हजार करोड़ खर्च कर प्रति वैक्सीन 700 रुपये की दर से 50 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन किया जायेगा। इसके साथ ही इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण यथा सड़क, पुल, एयरपोर्ट, बंदरगाह, बिजली आदि पर 5 लाख 540 करोड़ रूपये सरकार खर्च करेगी। चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व संग्रह में कमी के बावजूद सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर पर 4 लाख 39 हजार करोड़ रूपये खर्च किया है। जल-जीवन मिशन (शहर) के तहत अगले पांच वर्षों में 2 लाख 87 हजार करोड़ खर्च कर 2 करोड़ 86 लाख घरों को नल के जल से जोड़ा जायेगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1 लाख 41 हजार करोड़ कचरा प्रबंधन, प्रदूषण नियंत्रण आदि पर खर्च किये जाएंगे।

इस अवसर पर चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री सुनील सराफ, श्री आलोक पोद्दार, श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री सुबोध जैन, गणेश कुमार खेमका, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, आईसीएसआई की चेयर पर्सन पूजा कसेरा सहित कई सदस्य तथा प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधि काफी संख्या में उपस्थित थे।

आईसीएसआई की चेयर पर्सन पूजा कसेरा के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात सेमिनार समाप्त हुआ।

चैम्बर ने स्वरोजगार हेतु आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 11 ठेले प्रदान किये

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयीं ओर क्रमशः माननीय सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रो. राजन गंडोत्रा, श्रीमती अंजु गंडोत्रा तथा सचिव श्रीमती सुष्मा रिटोलिया। बाँयी ओर रोटरी क्लब ऑफ पाटलीपुत्रा के अध्यक्ष श्री विनोद चौधरी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 6 फरवरी 2021 को चैम्बर के सौजन्य से स्वरोजगार हेतु आर्थिक रूप से कमजोर 11 लोगों को माननीय सांसद (राज्य सभा) एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री सुशील कुमार मोदी के कर कमलों से प्रदान किया गया। इस अवसर पर रोटरी क्लब

ऑफ पाटलिपुत्र, बिहार-झारखण्ड के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोट. राजन गंडोत्रा एवं उनकी पत्नी श्रीमती अंजु गंडोत्रा उपस्थित थी।

चैम्बर अध्यक्ष ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि ठेला देने का उद्देश्य बेरोजगार, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वरोजगार से जोड़ना है। इससे वे सब्जी, फल, चाय, नास्ता एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री कर अपना तथा अपने परिवार का जीविकोपार्जन कर सकेंगे। श्री अग्रवाल ने कहा कि भविष्य में भी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वरोजगार हेतु ठेला प्रदान किया जायेगा। इसके संचालन की जिम्मेवारी रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्र को दिया गया है।

कार्यक्रम में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, पूर्व उपाध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री सुनील सराफ, श्री आलोक पोद्दार, श्री रामाशंकर प्रसाद, श्री सुबोध जैन, गणेश कुमार खेमका, श्री पशुपतिनाथ पाण्डेय, रोटरी क्लब ऑफ पाटलिपुत्र के अध्यक्ष बिनोद चौधारी, सचिव श्रीमती सुष्मा रिटोलिया, कोषाध्यक्ष श्री संतोष बंका, पूर्व सचिव श्री अनिल रिटोलिया सहित कई सदस्य उपस्थित थे।

स्वरोजगार हेतु निम्नांकित लोगों को ठेला प्रदान किया गया :-

श्रीमती मीना देवी को ठेला प्रदान करते माननीय सांसद एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री, बिहार श्री सुशील कुमार मोदी, चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, रोटरी गवर्नर रो. राजन गंडोत्रा, सचिव श्रीमती सुष्मा रिटोलिया एवं अन्य।

चैम्बर से प्रदत्त ठेला के साथ नजमा खातून

चैम्बर से प्रदत्त ठेला के साथ मो० जावेद

चैम्बर से प्रदत्त ठेला के साथ श्रीमती लक्ष्मी देवी

चैम्बर से प्रदत्त ठेला के साथ श्रीमती मीना देवी

चैम्बर से प्रदत्त ठेला के साथ श्री राघो राम

चैम्बर से प्रदत्त ठेला के साथ श्रीमती पूनम कुमारी

चैम्बर से प्रदत्त ठेला के साथ श्रीमती रिंकू देवी

चैम्बर से प्रदत्त ठेला के साथ रूकसाना खातून

चैम्बर से प्रदत्त ठेला के साथ श्री आनन्द मोहन (बाँये)

चैम्बर से प्रदत्त ठेला के साथ श्री टुनटुन चौधरी

उद्योग एवं सूचना प्रावैधिकी संबंधित उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व बैठक में चैम्बर द्वारा ज्ञापन प्रस्तुत

टैक्सेशन संबंधित समस्याओं पर बजट पूर्व बैठक की अध्यक्षता करते माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, विभागीय अधिकारीगण तथा चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यगण।

सचिवालय सभागार में उद्योग एवं सूचना प्रावैधिकी सेक्टर से संबंधित बजट पूर्व बैठक दिनांक 08 फरवरी 2021 को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित हुई। उक्त बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा सुझाव दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि समर्पित ज्ञापन के सुझावों पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार कर उचित निर्णय लिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार सरकार नव उद्यमियों एवं उद्यमिता के विकास हेतु कृत संकल्पित है। उनकी समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर सरकार समाधान करेगी।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने इस अवसर पर उद्योग सेक्टर के सुधार हेतु कई सुझाव दिए, जो निम्न हैं :-

- औद्योगिक विकास निधि का गठन
- जीएसटी प्रतिपूर्ति के दावों के निपटारे हेतु बजट में पर्याप्त राशि की व्यवस्था करना
- औद्योगिक भूखंडों की दर कृषि योग्य भूमि के समतुल्य करने
- सरकारी खरीद में स्थानीय वस्तुओं की भागेदारी सुनिश्चित करने
- एमएसएमई के भुगतान को प्राथमिकता देने तथा जिस प्रकार वस्तुओं की आपूर्ति में विलंब होने पर भी विलंब शुल्क लिया जाता है उसी प्रकार भुगतान में विलंब होने पर भी विलंब शुल्क एवं दण्ड का प्रावधान करने
- बैंकों को ऋण प्रवाह बढ़ाने का निर्देश देने
- पब्लिक सेक्टर बैंक का मुख्यालय बिहार में स्थापित करने
- चाय उद्योग के लिए प्रोत्साहन नीति घोषित करने
- पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर बिहार में बिजली की दर निर्धारित करने
- दिल्ली की तर्ज पर औद्योगिक प्रोपर्टीज की खरीद पर सर्किल रेट कम करने
- सर्विस सेक्टर को प्राथमिक क्षेत्र में रखने
- डैम का निर्माण कर पनबिजली उत्पादित करने
- पर्यटन, स्टार्टअप क्षेत्र का विकास करने
- खाद्य एवं खाद्य प्रसंस्करण आधारित उत्पादों के निर्यात हेतु संस्था का गठन करने सहित कई अन्य सुझाव

इसके अतिरिक्त श्री अग्रवाल ने आईटी सेक्टर के विकास हेतु टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कम्पनियों के विकास केंद्र बिहार में स्थापित करने, आईटी सेक्टर को औद्योगिक प्रोत्साहन निति में शामिल करने, आईटी पार्क संबंधित कार्यों की समीक्षा करने का भी सुझाव दिया।

बैठक में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, वरीय सदस्य श्री आलोक पोद्दार, श्री ए.के.पी. सिन्हा तथा श्री राजीव अग्रवाल भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, पटना द्वारा "केंद्रीय बजट 2021–22" विषय पर आयोजित वेबिनार में हुए शामिल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रलय, भारत सरकार के प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी), पटना द्वारा दिनांक 11 फरवरी 2021 को **'केंद्रीय बजट 2021-22'** विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल भी विशेष रूप से आमंत्रित थे।

वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए पीआईबी के अपर महानिदेशक श्री एस.

प्रेस इन्फॉमेशन ब्युरो पटना द्वारा "केन्द्रीय बजट 2021-22" पर आयोजित वेबिनार में शामिल चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल (प्रथम पंक्ति में मध्य) एवं अन्य वक्तागण।

के. मालवीय ने कहा कि वर्ष 2020 की तमाम चुनौतियों के बीच यह एक एतिहासिक बजट है, जो पूरी तरह से स्वागत योग्य है। निस्संदेह यह एक अच्छा बजट साबित होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा बजट में खास तौर पर सामाजिक क्षेत्र पर अत्यधिक महत्व दिया गया है। एमएसएमई, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जिस पर केंद्रीय बजट में विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि 2021-22 के बजट में आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य एवं सेहत पर अधिक फोकस किया गया है। यह एक स्वागत योग्य बजट है। यह विकास को गति देने वाला और आधारभूत संरचना को बनाने वाला बजट है।

श्री अग्रवाल ने कहा कि एक समय था जब बजट को केवल नई ट्रेनों के परिचालन, नये स्टेशनों के निर्माण आदि तक ही सीमित समझा जाता था। लेकिन विगत बर्षों से यह देखने को मिल रहा है कि अब स्वास्थ्य, सेहत और शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।

वेबिनार को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। धन्यवाद ज्ञापन फील्ड आउटरिच ब्यूरो, छपरा के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी श्री पवन कुमार सिन्हा ने किया।

चैम्बर प्रतिनिधिमंडल पथ निर्माण मंत्री से मिला

माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन को पुष्पगुच्छ से सम्मानित करते चैम्बर प्रतिनिधिमडंल के सदस्यगण।

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर के नेतृत्व में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 24 फरवरी 2021 को बिहार के माननीय पथ निर्माण मंत्री श्री नितिन नवीन से उनके कार्यालय में मिलकर एवं पुष्पगुच्छ से उनका अभिनन्दन किया साथ ही उन्हें चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट किया।

प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, वरीय सदस्य श्री ए० के० पी० सिन्हा, श्री आलोक पोद्दार एवं श्री राजेश माखरिया शामिल थे।

माननीय पथ निर्माण मंत्री को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर प्रतिनिधिमडंल के सदस्यगण।

आम बजट 2021-2022 पर चैम्बर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

बड़े कारोबारियों को विशेष राहत नहीं

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बजट को मिला-जुला बताया है। बिहार चैम्बर का कहना है कि इस बार के बजट में सरकार ने स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर एवं रिफॉर्म पर फोकस करते हुए अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का प्रयास बताया है। चैम्बर अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने कहा है कि भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोविड-19 के कारण बजट पेपरलेस तरीके से पेश किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इस बजट में आर्थिक मंदी से उबारने पर विशेष जोर है। बिहार के स्तर पर देखा जाए तो बिहार की आम जनता के साथ-साथ राज्य के उद्यमियों और व्यवसायियों को बजट से निराशा हाथ लगी है।

सब्सिडी देने की मांग : राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने की मांग भी चैम्बर ने की थी। राज्य में पाँच सितारा होटल की स्थापना के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में कम से कम 5 साल के लिए टैक्स छूट की बात चैम्बर की से पूर्व में कही गई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे व्यवसायी हैं, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, उन्हें सब्सिडी मिले।

जीएसटी मित्र बनाएँ : जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर सरकार की और से जीएसटी मित्र बनाने की मांग और निर्बंधित को नि:शुल्क सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराने की मांग भी चैम्बर ने की है। चैम्बर का कहना है कि बजट में घोषणा से किसानों और छोटे व मध्यम वर्गीय लोग जरूर लाभान्वित होंगे।

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.2.2021)

(कृपया पृष्ठ-11 भी देंखे)

बिहार चैम्बर में माननीय श्रम संसाधन मंत्री के अभिनन्दन समारोह में चैम्बर शामिल

कार्यक्रम का संयुक्त रूप से दीप प्रज्जवलित कर उद्घाटन करते
माननीय श्रम संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री जिवेश कुमार एवं चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य।

चैम्बर द्वारा निःशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करते माननीय श्रम संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री जिवेश कुमार।
साथ में हैं चैम्बर के पदाधिकारीगण ।

चैम्बर द्वारा संचालित फिजियोथेरेपी सेन्टर का अवलोकन करते माननीय श्रम संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री जिवेश कुमार।
साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण।

चैम्बर द्वारा संचालित फिजियोथेरेपी सेन्टर का अवलोकन करते माननीय श्रम संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री। साथ में चैम्बर के पदाधिकारीगण।

माननीय श्रम संसधान तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री श्री जिवेश कुमार को चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन। साथ में वरीय सदस्य श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं अन्य ।

दिनांक 19 फरवरी 2021 को उड़ान सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा बिहार चैम्बर के प्रांगण में श्री जिवेश कुमार, माननीय श्रम संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री का नागरिक अभिनन्दन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री एन० के० ठाकुर एवं श्री मुकेश कुमार जैन, महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, वरीय सदस्य श्री शशि मोहन, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं श्री रंजीत प्रसाद सिंह सम्मिलित हुए। माननीय श्रम संसाधन तथा विज्ञान एवं प्रावैधिकी मंत्री ने चैम्बर द्वारा महिलाओं के लिए संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र एवं फिजियोथेरेपी सेन्टर का भी अवलोकन किया।

इस अवसर पर माननीय मंत्री जी को चैम्बर की ओर से चैम्बर कॉफी टेबुल बुक भी प्रदान किया गया।

चैम्बर द्वारा मिठाई, नमकीन एवं स्नैक्स के निर्माताओं के साथ बैठक

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2021 को मुम्बई के मिठाई, नमकीन, एवं स्नैक्स के निर्माताओं की शीर्ष संस्था फेडेरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्यूफैक्चरर्स, के साथ बैठक आयोजित हुई।

चैम्बर की ओर से उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन ने फेडेरेशन के अधिकारियों का स्वागत करते हुए कहा कि पटना में मिठाई, नमकीन, एवं स्नैक्स के निर्माताओं की यह पहली बैठक हो रही है और इस बैठक का उद्देश्य पटना में मिठाई, नमकीन एवं स्नैक्स के निर्माताओं की हो रही परेशानी एवं उन्हें कैसे

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन। उनकी बाँयी ओर मिठाई नमकीन निर्माता फेडरेशन के डायरेक्टर फिरोज हैदर नकवी, चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, फेडरेशन के श्री बिनोद प्रसाद भदानी। दाँयीं ओर हल्दीराम ग्रुप के डायरेक्टर श्री सुशील जैन एवं फुड सेफ्टी ऑफिसर श्री अजय कुमार।

फेडरेशन के डायरेक्टर फिरोज हैदर नकवी को पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र से स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं अन्य

हल्दीराम ग्रुप के डायरेक्टर श्री सुशील जैन को अंगवस्त्र से स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन साथ में फूड सेफ्टी ऑफिसर श्री अजय कुमार।

फेडरेशन के डायरेक्टर फिरोज हैदर नकवी को मेमेन्टो एवं कॉफी टेबुल बुक भेंट करते चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

हल्दीराम ग्रुप के डायरेक्टर श्री सुशील जैन को मेमेन्टो भेंट करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी।

फुड सेफ्टी अधिकारी, पटना श्री अजय कुमार को मेनेन्टो भेंट करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन एवं महामंत्री श्री अमित मुखर्जी तथा हल्दीराम ग्रुप के डायरेक्टर श्री सुशील जैन।

चैम्बर द्वारा नि:शुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करते फेडरेशन के डायरेक्टर एवं हल्दीराम गुप के डायरेक्टर। साथ में चैम्बर उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन।

अपग्रेड किया जाए, इस पर विस्तृत विचार-विमर्श करना है जिससे फेडेरेशन उनकी समस्याओं से संबंधित विभागों को अवगत करा सके।

फेडेरेशन के डायरेक्टर फिरोज हैदर नकवी एवं हल्दीराम ग्रुप के डायरेक्टर ने स्थानीय व्यवसायियों को सुझाव दिया कि मिठाई, नमकीन एवं स्नैक्स के पुराने तरीके को अपग्रेड करें। आज की तिथि में काफी नई-नई तकनीक आ गयी है जिसके माध्यम से मिठाइयों को पैक करके अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है साथ ही इस कार्य में नये पीढ़ी के लोगों को भी शामिल करें। ऐसा करने से आप स्थानीय स्तर पर बिक्री करने के साथ-साथ उसे

निर्यात भी कर सकते हैं। यदि आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में दो-चार विदेशी कम्पनियाँ मिठाई उद्योग को अपने हाथ में ले लेंगे। उन्होंने यहाँ के लोगों को गुजरात, हैदराबाद, राजस्थान आदि में नई-नई तकनीक से बनाए जा रहे मिठाईयाँ एवं नमकीन की फैक्ट्री को देखने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने टेस्टिंग हेतु स्थानीय स्तर पर लैब बनाने तथा मिठाई बनाने के हुनर को विकसित करने के लिए एक प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाने का भी सुझाव दिया।

बैठक में पटना के मिठाई, नमकीन एवं स्नैक्स के क्षेत्र में कार्य कर रहे व्यवसायी यथा - हरीलाल वेंचर, कोजी स्वीट्स, डैजी स्वीट्स, गोकुल, सोडा फाउंटेन, स्वीट होम, बिकानेर स्वीट्स, लड्डू गोपाल स्वीट्स, जलपान, चेरी स्वीट्स, प्रमोद लड्डू भंडार, हीरा स्वीट्स, कामधोनु स्वीट्स के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हुए।

कार्यक्रम में चैम्बर महामंत्री श्री अमित मुखर्जी ने फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड नमकीन मैन्यूफैक्चरर्स के अधिकारियों, श्री सुशील जैन, डायरेक्टर हल्दीराम ग्रूप एवं श्री अजय कुमार, फूड सेफ्टी ऑफिसर को मेमेन्टो एवं चैम्बर का कॉफी टेबुल बुक भी प्रदान किया।

चैम्बर द्वारा निशुल्क संचालित कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्र का अवलोकन करते फेडरेशन एवं हल्दीराम ग्रुप के डायरेक्टर्स। साथ में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जैन तथा अन्य।

बैठक में चैम्बर के महामंत्री श्री अमित मुखर्जी, वरीय सदस्य श्री व्यास मुनि ओझा, श्री पवन कुमार अग्रवाल (छपरा), श्री अब्दुल मुजीब अंसारी, फेडरेशन के पदाधिकारी फिरोज हैदर नकवी, आफताब हैदर जैदी एवं हल्दीराम ग्रुप के डायरेक्टर श्री सुशील जैन, हरीलाल वेंचर के श्री अमित मनकानी, श्री बिनोद प्रसाद भदानी, श्री अजय कुमार, फूड सेफ्टी ऑफिसर पटना के साथ- साथ प्रेस एवं मीडिया के बन्धु सम्मिलित हुए।

आम बजट 2021-2022 पर चैम्बर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

बिहार चैम्बर : बिहार को विशेष योजना या पैकेज नहीं मिलना निराशाजनक

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने केन्द्रीय बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना या पैकेज का प्रावधान नहीं करने को निराशजनक बताया है। अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा कि बिहार की आम जनता के साथ-साथ राज्य के उद्यमी और व्यवसायियों को आशा थी कि बजट में विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी, क्योंकि पूर्व में भाड़ा समानीकरण नीति और खनिजों पर रॉयल्टी के मद में राज्य को काफी नुकसान हुआ है। राज्य को हमेशा बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है।

केन्द्र सरकार से कई बार उत्तर बिहार को तीव्र औद्योगिकीकरण के लिए गैस पाइपलाइन से जोड़ने और विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए 5 साल के लिए करावकाश देने की मांग की गई थी। हालांकि सरकार ने स्वास्थ्य, इन्फ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म पर फोकस डालते हुए अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का प्रयास किया। **(साभार : दैनिक भास्कर, 2.2.2021)**

TRADE & INDUSTRY BODIES HAIL BUDGET

The trade and industry bodies in the state appreciated the Union Budget, saying that it would have a positive impact on the overall economy. But they lamented that there was nothing concrete for Bihar in it.

Bihar Chamber of commerce and Industries (BCCI) president P. K. Agarwal said the Budget, from a national perspective, is likely to pull the slumping economy and benefit the far mere and the middle class people. "But people in the state had expectations of special schemes or special status for Bihar. The state has already suffered because of freight policy and royalty on minerals and it faces floods and drought every year." he said. Agarwal said the BCCI had sent a memorandum to the Union finance minister requesting for special support to Bihar for attracting big players to set up aluminium, petrochemical and other big industries, besides relaxations in direct and indirect taxes for opening 5-star hotels. **(Source : Times of India, 2.2.2021)**

आम बजट से अर्थव्यवस्था को मिलेगी तेज गति

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने बजट को स्वास्थ्य, संसाधन एवं रिफॉर्म पर फोकस करने और अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने वाला बताया है। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल ने कहा कि इतिहास में पहली बार कोविड के कारण पेपरलेस तरीके से बजट पेश किया गया। बजट में आर्थिक मंदी को उबारने पर जोर दिया गया है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास के लिए विशेष योजना या पैकेज की उम्मीद थी। चैम्बर ने वित्त मंत्री को ज्ञापन भेजकर कई मांगें रखी थीं। इसमें राज्य में स्टील, एल्युमिनियम, पेट्रोकेमिकल आदि उद्योग लगाने की मांग की गई थी। जबतक राज्य में कल-कारखाने नहीं खुलेंगे, तब तक विकास संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बजटीय घोषणाओं से किसान एवं छोटे व मध्यवर्गीय लोग लाभान्वित होंगे। राज्य के लिए कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से निराशा हुई है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में केन्द्रीय बजट सराहनीय है। **(साभार : दैनिक जागरण, 2.2.2021)**

अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का है प्रयास

संसद में पेश आम बजट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि इस बार में सरकार ने स्वास्थ्य, इफ्रास्ट्रक्चर एवं रिफार्म पर फोकस करते हुए अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने का प्रयास किया है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण बजट पेपर लेस तरीके से पेश किया गया है। यदि राष्ट्रीय स्तर पर इस बजट को देखा जाए तो महामारी के कारण देश में आयी आर्थिक मंदी से उबारने पर विषेश जोर दिया गया है, परन्तु यदि बिहार के स्तर पर देखा जाए तो बिहार की आम जनता के साथ राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायियों को आशा थी कि इस बार के बजट में बिहार जैसे पिछड़े राज्य के आर्थिक विकास हेतु अपेक्षित विशेष योजना या विशेष पैकेज की घोषणा की जाएगी, क्योंकि पूर्व में भाड़ा समानीकरण नीति एवं खनिजों पर रॉयल्टी के मद में राज्य को काफी नुकसान हुआ है। साथ ही राज्य को हमेशा बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। बजटीय घोषणाओं से किसानों एवं छोटे व मध्यमवर्गीय लोग लाभाविन्त होंगे। हालांकि बिहार राज्य के लिए इस बजट में कोई विशेष प्रस्ताव नहीं होने से हमलोगों को थोड़ी निराशा जरूर हुई है, परन्तु राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में सम्पूर्ण सामाजिक उत्थान के हिसाब से इस बजट को सराहनीय कहा जा सकता है।

– पी. के. अग्रवाल, अध्यक्ष, बी.सी.सी.आई. **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 2.2.2021)**

केन्द्रीय बजट में सरकारी रुपये का हिसाब-किताब

रुपया कहाँ से आएगा : • 8 पैसे : केन्द्रीय उत्पाद • 14 पैसे : आय कर • 13 पैसे : निगम कर • 36 पैसे : उधार और अन्य देयताएँ • 3 पैसे : सीमा शुल्क • 6 पैसे : कर भिन्न राजस्व • 15 पैसे : उत्पाद और सेवा कर • 5 पैसे : ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियाँ

कहाँ जाएगा : • 9 पैसे : केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएँ • 13 पैसे : केन्द्रीय क्षेत्र की योजना • 20 पैसे : ब्याज अदायगी • 8 पैसे : रक्षा • 9 पैसे : आर्थिक सहायता • 10 पैसे : वित्त आयोग और अन्य अंतरण • 16 पैसे : करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा • 5 पैसे : पेंशन • 10 पैसे : अन्य व्यय

बजट एक नजर में

(सभी राशि करोड़ रुपये में हैं)

विषय	2019-20 वास्तविक	2020-21 अनुमान	2020-21 स. अनुमान	2021-22 बजट अनुमान
1. राजस्व प्राप्तियाँ	16,84,059	20,20,926	15,55,153	17,88,424
2. कर राजस्व	13,56,902	16,35,909	13,44,501	15,45,396
3. कर भिन्न राजस्व	3,27,157	3,85,017	2,10,652	2,43,028
4. पूंजी प्राप्तियाँ	10,02,271	10,21,304	18,95,152	16,94,812
5. ऋणों की वसूली	18,316	14,967	14,497	13,000
6. अन्य प्राप्तियाँ	50,304	2,10,000	32,000	1,75,000
7. उधार और अन्य देयताएँ	9,33,651	7,96,337	18,48,655	15,06,812
8. कुल प्राप्तियाँ (1+4)	26,86,330	30,42,230	34,50,305	34,83,236
9. कुल व्यय (10+13)	26,86,330	30,42,230	34,50,305	34,83,236
10. राजस्व खाते पर	23,50,604	26,30,145	30,11,142	29,29,000
11. ब्याज भुगतान	6,12,070	7,08,203	6,92,900	8,09,701
12. पूंजी संपत्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान	3,35,726	4,12,085	4,39,163	5,54,236
13. पूंजी खाते पर	6,66,545	6,09,219	14,55,989	11,40,576
14. राजस्व घाटा (10-1)	4,80,904	4,02,719	12,25,613	9,21,464
15. प्रभावी राजस्व घाटा (14-12)	9,33,651	7,96,337	18,48,655	15,06,812
16. राजकोषीय घाटा (9-(1+5+6))	3,21,581	88,134	11,55,755	6,97,111
17. प्राथमिक घाटा (16-11)				

केन्द्र सरकार का व्यय बजट अनुमान 2021-22

मद	राशि	मद	राशि
पेंशन	1,89,328	ब्याज	8,09,701
रक्षा	3,47,088	सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरसंचार	53,108
मुख्य अनुदान	3,35,361	योजना एवं सांख्यिकी	2,472
कृषि एवं कृषि संबंधी	1,48,301	ग्रामीण विकास	1,94,633
व्यापार एवं उद्योग	34,623	वैज्ञानिक विभाग	30,640
पूर्वोत्तर राज्यों के विकास पर	2,658	सामाजिक कल्याण	48,460
		कर प्रशासन	1,31,100
शिक्षा	93,224	राज्यों को हस्तांतरित	2,93,302
ऊर्जा	42,824	परिवहन	2,33,083
विदेशी मामले	18,155	केन्द्र शासित	53,026
वित्त	91,916	शहरी विकास	54,581
स्वास्थ्य	74,602	अन्य	87,528
गृह मामले	1,13,521	**कुल योग**	**34,83,236**

(साभार : दैनिक जागरण, 2.2.2021)

आम बजट 2021–22 की खास बातें

भारत का बजट प्रस्ताव पिलर्स पर आधारित है। जिसमें स्वास्थ्य और जन कल्याण, कैपिटल इंफास्ट्रकर, इनोवेशन एंड आरएंड डी, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नमेंस, ह्युमन कैपिटल, डेवलेपमेंट ऑफ एसपिरेशनल इंडिया शामिल है।

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 5.54 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के मुकाबले 34.5 फीसदी ज्यादा है।
- बजट में जल जीवन मिशन के तहत 2.87 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की गई है।
- वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 42 अर्बन सेंटर्स में 2217 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे।
- कोविड 19 वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है।
- बजट में नेशनल इंफ्रास्ट्रकर को मजबूत करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। जिसमें देशभर में 217 प्रोजेक्ट पूरे किए जाएंगे।
- अगले तीन साल में देश में 7 टैक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे।
- इस साल सरकार ने देशभर में 11 हजार किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके तहत तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में बड़े राजमार्ग प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू किया जाएगा। 1001 किलोमीटर 65 हजार करोड़ जिसमें मुम्बई कन्याकुमारी हाइवे भी शामिल है। 25 हजार करोड़ से कोलकाता से सिलीगुड़ी रोड को ठीक किया जाएगा।
- रेलवे के लिए सरकार ने बजट में 1.10 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इनमें से 1.7 लाख करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए होंगे। रेलवे ने नेशनल रेल प्लान तैयार किया है। जिसके तहत 2030 तक वेस्टर्न डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर, इटारसी टु विजयवाड़ा आदि प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा।
- पब्लिक बसों के लिए सरकार ने बजट में 18 हजार करोड़ रुपए का ऐलान किया है।
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर बजट में बंदरगाहों में सुधार के लिए 2000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है।
- उर्जा क्षेत्र के लिए बजट में 3.05 लाख करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है।
- उज्जवला योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को इसका फायदा दिया जाएगा। अगले तीन सालों में गैस डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क के तहत 100 और शहरों में इसका फायदा मिलेगा। जम्मू कशमीर में भी गैस पाइपलाइन का काम शुरू किया जाएगा। अक्षय उर्जा को बढावा देने के लिए सरकार ने सोलर एनर्जी के लिए 1000 करोड़ और रिन्यूबल ऊर्जा के लिए 1500 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है।
- बीमा क्षेत्र में एफडीआई (विदेशी निवेश) को 49% से बढ़ाकर 74% किया जाएगा। सरकार ने निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का भी ऐलान किया है। सरकारी बैंकों को बजट में 20 हजार करोड़ रुपए दिए जांएगे।
- सरकार ने सभी गैर रणनीतिक और रणनीतिक सेक्टर्स में निवेश घटाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सरकार 2022 में एलआईसी का आईपोओ लाएगी। दो सार्वजनिक बैंकों और एक सार्वजनिक इंश्योरेंस कंपनी में निवेश घटाने का प्रस्ताव दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2022 में सरकार ने

डिसइन्वेस्टमेंट से 1.75 लाख करोड़ रुपए का राजस्व इकट्ठा करने का लक्ष्य तय किया है।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने गेहूँ उगाने वाले किसानों को 75 हजार करोड़ का भुगतान किया। जिससे देश के 43.36 लाख किसानों को फायदा हुआ। 2020-21 में धान उगाने वाले किसानों को 1.72 लाख करोड़ दिए गए। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट को बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ किया जाएगा।
- काबुली चने पर 30%, मटर पर 10%, बंगाली चने पर 50% और मसूर दाल पर 20%, कॉटन पर 5% एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। इनके अलावा सोने, चाँदी पर 2.5%, सेबों पर 35%, कुछ फर्टिलाइजर्स पर 5%, कोयले लिग्नाइड पर 1.5% सेस लगाया गया है। सूरजमुखी तेल, सोयाबीन तेल पर 20% और क्रूडपाम ऑयल 17.5% सेस लगाया गया है।
- इनके अलावा प्रति लीटर पेट्रोल पर 2.5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए प्रति लीटर का फार्म सेस लगेगा।
- बजट में असम और बंगाल के टी वर्कर्स के लिए 1000 करोड़ का ऐलान किया गया है।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी का 9.5% रहा। वहीं वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए राजकोषीय घाटा 6.8% रहेगा।

(साभार : आज, 2.2.2021)

केन्द्रीय बजट 2021–22 में सस्ता–महँगा

सस्ता : • चमड़े के उत्पाद • ड्राई क्लिनिंग • पेंट • लोहे के उत्पाद • स्टील के बर्त्तन • इंश्योरेंस • बिजली • सोना-चांदी • जूता • नायलॉन • पॉलिस्टर • कृषि उपकरण

महँगा : • मोबाइल और चार्जर • तांबे का सामान • सूती कपड़े • इलेक्ट्रोनिक सामान • रत्न • सौर इनवर्टर • सेब • यूरिया • काबुली चना • डीएपी खाद • चना दाल • पेट्रोल-डीजल • शराब • ऑटो पार्ट्स

(साभार : जनसत्ता : 2.2.2021)

छोटे कारोबारियों को तीन साल का ही रखना होगा लेनदेन का रिकॉर्ड

छोटे कारोबारियों को अब तीन साल तक के लेनदेन का ही रिकॉर्ड रखना होगा। वर्तमान में कारोबारियों को छह साल तक का रिकॉर्ड रखने का प्रावधान है। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बजट में समय सीमा को घटा दिया है, इससे कारोबारियों को काफी राहत मिलने की संभावना है। ये बातें बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अध्यक्ष पी. के. अग्रवाल ने बजट का विशलेषण करने के बाद कहीं।

उन्होंने बताया कि इसी तरह अब तक केवल दो करोड़ तक का कारोबार करने वाली कंपनी को ही छोटी कंपनी के दायरे में रखा जाता था। अब इसे बढ़ाकर 20 करोड़ तक कर दिया गया है। इससे छोटे कारोबारियों को पारदर्शी तरीके से कारोबार करने में मदद मिलेगी। अग्रवाल ने बताया कि डिसप्यूट रिजोल्यूशन कमिटी बनाने की घोषणा की गयी है। इससे कारोबारियों को लंबे समय तक कोर्ट-कचहरी का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।

उन्होंने बताया कि सरकार के दावे के बावजूद जीएसटी व्यवस्था में सरलीकरण नहीं हुआ। इसका जितना अधिक सरलीकरण होगा, इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और कर का दायरा भी बढ़ेगा। साथ ही उन्होंने, बताया कि बजट में खुदरा व्यापार को योजनाबद्ध तरीके से विकसित करने और आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाने की जरूरत थी।

(साभार : प्रभात खबर, 4.2.2021)

बिहार बजट 2021–22 की दस बड़ी बातें

बिहार विधानसभा में दिनांक 22 फरवरी 2021 को राज्य के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि बिहार में इस बार का बजट 2 लाख 18 हजार 303 करोड़ रुपये का है, जिसमें विकास योजना मद में 1, 0051.86 करोड़ रुपये एवं स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,17,783.84 करोड़ रुपये हैं। तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि सरकार को इस साल 2 लाख 18 हजार 502 करोड़ 70 लाख की अनुमानित आय की प्रप्ति होगी।

- राज्य सरकार ने बजट में ऐलान किया है कि अब अगर अविवाहित महिला इंटर पास करती है तो उसे 25 हजार रुपए दिए जाएँगे। साथ ही स्नातक उतीर्ण होने पर उसे 50 हजार रुपए दिए जाएँगे। सरकार द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35 फीसदी आरक्षण, सरकारी ऑफिस में आरक्षण के अनुरूप संख्या बढ़ाई जाएगी। महिलाओं को उद्योग के लिए 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा।
- वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सात निश्चय पार्ट 2 के लिए 4671 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान किया गया है। युवाओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी जिससे रोजगार सृजित हो। बिहार के युवा उद्यमी बने इसके लिए व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में गुणवत्ता बढ़ाये जा रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की योजना है। चिकित्सा और अभिंयत्रण के महाविद्यालय स्पेशल स्किल के साथ खोले जाएँगे। इसके साथ खेल विश्व विद्यालय की स्थापना की जा रही है।
- राज्य सरकार ने बजट में बाल हृदय योजना के लिए भी राशि का प्रावधान किया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि छोटे बच्चे के हृदय में छेद को लेकर बनाया गया है और इसे लागू कर दी गई है। इसके लिए 300 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
- वित्त मंत्री ने सदन को बताया कि जनसंख्या वृद्धि को लेकर जाम की समस्या है। शहरों में जाम से स्थिति गंभीर है, इसे दूर करने के लिए बाईपास का निर्माण किया जाएगा। 200 करोड़ रुपये की राशि का इसके लिए प्रावधान किया गया है। टेलीमेडिशन की योजना को हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। गंभीर बीमारी के साथ पैथोलॉजी जाँच की व्यवस्था का जा रही है।
- ताराकिशोर प्रसाद ने कहा कि मछली पालन और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये राशि व्यय का प्रावधान किया गया है। शहर में रह रहे भूमिहीन को घर बनाने के लिए सुविधा के साथ घाट पर अंतिम

बिहार बजट 2021 पर चैम्बर अध्यक्ष की प्रतिक्रिया

बजट आकार में वृद्धि सराहनीय पर कई सुझावों पर विचार नहीं

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के अनुसार बजट के प्रावधानों से स्पष्ट है कि सरकार अधिकाधिक रोजगार सृजन की मंशा रखती है। हालांकि, बजट पूर्व चैम्बर की ओर से दिए गए कई सुझावों पर भी विचार करना चाहिए था। चैम्बर के अध्यक्ष पी. के अग्रवाल के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रामीण विकास और महिलाओं पर बजट में विशेष ध्यान दिया गया है। रोजगार सृजन की भी बात कही गई है। इसके लिए अधिक से अधिक उद्योग स्थापित करने के लिए रोडमैप तैयार करना होगा। कोरोना काल में आय में कभी के बावजूद पिछले वर्ष की तुलना में इस साल के बजट में करीब तीन फीसद की वृद्धि की गई। इससे राज्य के विकास को गति मिलेगी। कौशल एवं उद्यमिता विकास के लिए अलग से विभाग की स्थापना सराहनीय है। बजट से पूर्व हमारी मांग थी कि उद्योग विभाग का बजट 2000 करोड़ रुपये किया जाए ताकि क्लेम का निपटारा हो सके। साथ ही औद्योगिक विकास निधि का गठन करने, लैंड बैंक बनाने, बैंक ऋण का प्रवाह बढ़ाने, पर्यटन को बढ़ावा देने, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए निर्यात संस्थान का गठन करने, विद्युत दर पड़ोसी राज्यों के समतुल्य करने, बियाडा की ओर से दी गई जमीन को फ्री होल्ड करने की मांग की गई थी। इनपर भी विचार करना चाहिए था। **(साभार : दैनिक जागरण, 23.2.2021)**

संस्कार के लिए मोक्षधाम का निर्माण। इसके लिए 450 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

- बिहार में सोलर लाइट लागने के लिए पंचायती राज विभाग को 150 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान, लोहिया स्वक्षता योजना 2 के लिए 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रोत्साहन राशि से सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव आयेगा।
- बिहार सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था की है। हर खेत में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। हर खेत में पानी पहुँचाने की योजना के लिए 550 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। राज्य के सभी गाँवों में सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए 150 करोड़ का बजट में प्रावधान किया गया है।
- राज्य में गोवंश विकास की स्थापना की जाएगी। पशुओं के इलाज के लिए कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप इलाज की व्यवस्था की जाएगी और यह सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से मिलेगी। बिहार में मछली उत्पादन को बढ़या जाएगा, ताकि यहाँ की मछली दूसरे राज्यों में जाए।
- बिहार के सभी शहरों में जलजमाव की समस्या को दूर करने के लिए 450 करोड़ राशि का प्रावधान बजट में किया गया है। बुजुर्गो के लिए आश्रय स्थल बनाए जाएँगे, बजट में इसके लिए 90 करोड़ की व्यवस्था की गई।
- तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि गाँवों में संपर्क सड़क बनाने की योजना है। इस योजना पर 250 करोड़ का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में बाईपास और फ्लाई ओवर बनाये जाएँगे। इसके लिए बजट में 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

(साभार : आज, 23.2.2021)

एग्री इंफ्रा सेस का एलान, 2 फरवरी से लागू

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में, कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कुछ चीजों पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट सेस लगाने का एलान किया। यह नया एग्री इंफ्रा सेस मंगलवार (2 फरवरी, 2021) से लागू होगा। कच्चे तेल पर 17.5% कृषि सेस, कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर 20% का सेस लगाया है। ग्राहकों पर कीमतों का अतिरिक्त भार न पड़े इसके लिए इन पर बेसिक सीमा शुल्क (बीसीडी) में कटौती की गयी है। इन चीजों में सेब (15%), एल्कोहॉलिक पेय पदार्थ (50%), कच्चे खाद्य तेल (15%), कोयला (1%), अमोनियम नाइट्रेट (2.5%), मटर, काबुली चना, बंगाल चना, मसूर (10%) फीसदी शामिल हैं।

2.5 प्रतिशत से 100 फीसदी तक लगाया गया सेस

उत्पाद	एग्री इंफ्रा सेस	उत्पाद	एग्री इंफा सेस
क्रूड पाम ऑइल	17.5%	कोयला	1.5%
क्रूड सोयाबीन	20%	काबुली चना	30%
सूरजमुखी	20%	मटर	10%
एल्कोहॉलिक पेय पदार्थ	100%	चना	50%
गोल्ड, सिल्वर और डोर बार	2.5%	मसूर	20%
सेब	35%	पेट्रोल	2.5 रु० प्रति लीटर
स्पेसिफाइड फर्टिलाइजर	05%	डीजल	4. रु० प्रति लीटर

(साभार : प्रभात खबर, 2.2.2021)

रेल बजट में इस बार पूर्व मध्य रेलवे को मिले 4843 करोड़

पिछली बार की तुलना में 229 करोड़ अधिक मिले, दोहरीकरण मद में तीन गुना से अधिक राशि

केन्द्रीय बजट में पेश रेल बजट में इस बार पूर्व मध्य रेल को 4843 करोड़ को आवंटन किया गया है। पिछली बार की तुलना में इस बार 229 करोड़ अधिक मिले हैं। रेलवे में बिहार का अधिकतर हिस्सा पूमरे के ही दायरे में आता है। अर्थात, इस पैसे से ही बिहार की महत्वपूर्ण रेल परियोजनाओं पर काम होगा। वैसे रेल प्रशासन राज्यवार राशि का भी ब्योरा जारी किया करता है।

बिहार को मिलने वाली राशि का अलग से ब्योरा जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के अनुसार पिछली बार की तुलना में इस बार कई मदों में अधिक पैसे दिए गए हैं। पिछली बार नई रेल लाइन के लिए मात्र 459 करोड़ दिए गए थे। इस बार यह राशि बढ़ाकर 596 करोड़ कर दी गई है। इसी तरह छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने के काम आमान परिवर्तन के मद में पिछली बार 173 करोड़ मिले थे। इस बार इसे 190 करोड़ किया गया है। रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण में इस बार तीन गुना से अधिक राशि दी गई है। पिछली बार मात्र 52 करोड़ दोहरीकरण मद में मिले थे। इस बार 182 करोड़ दिए गए हैं।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए राशि : • 150 करोड़ सकरी-सहरसा-फारबिसगंज रेल लाइन • 100 करोड़ जयनगर-नेपाल रेल लाइन के लिए • 95 करोड़ मुंगेर गंगा पुल के लिए • 50 करोड़ पटना गंगा पुल का विद्युतीकरण • 60 करोड़ रुपए कोसी पुल के लिए • 15 करोड़ मानसी-मधेपुरा-पूर्णिया ट्रैक के लिए • 25 करोड़ जयनगर-नरकटियागंज ट्रैक के लिए

नई रेल लाइन व सुरक्षा पर ज्यादा खर्च करेगा पूमरे : पूर्व मध्य रेलवे में इस बार सबसे ज्यादा राशि नई रेल लाइनों के निर्माण, गेज परिवर्तन और सुरक्षा पर खर्च की जाएगी। सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि उपरोक्त कार्यो के अलावा रेलवे ट्रैफिक सिग्नल प्रणाली में सुधार, रेलवे स्टेशनों व ट्रेनों में यात्री सुविधा में विस्तार समेत कई अन्य कार्य किए जाएँगे।

कई कार्यों के लिए बढ़ा कर मिली है राशि : संरक्षा मद में पिछली बार 191 करोड़ की तुलना में इस बार 206 करोड़ मिले हैं। जबकि रेलवे क्रॉसिंग यानी समपार के मद में पिछली बार 60 करोड़ की तुलना में 74 करोड़ राशि आवंटित की गई है। ट्रैक नवीनीकरण की राशि पिछली बार की तरह इस बार भी 580 करोड़ है। पिछली बार 154 करोड़ की तुलना में इस बार पूमरे को यात्री सुविधाओं पर खर्च करने के लिए 171 करोड़ दिए गए हैं। पूमरे के अधीन कारखानों के लिए इस बार अधिक राशि दी गई है। पिछली बार कारखाना मद में मात्र 111 करोड़ दिए गए थे तो इस बार 134 करोड़ मिले हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.2.2021)

विवाद समाधान समिति की कई शाखाएँ होंगी

• 50 लाख रुपए तक की कर योग्य आय वाले विवादित मामलों का निपटान करेगी समिति • दस लाख रुपए की विवादित आय के मामले भी निपटाएगी समिति • इससे छोटे करदाताओं को कानूनी झंझटों से मिलेगा छुटकारा • करदाताओं को नहीं करना पड़ेगा कठोर अपीलीय प्रक्रिया का सामना

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष पीसी मोदी ने कहा कि आम बजट में प्रस्तावित विवाद समाधान समित की कई शाखाएँ होंगी, जिससे छोटे करदाताओं को अपीलीय प्रक्रिया से गुजरे बिना कर मामलों को निपटाने का मौका मिलेगा।

मोदी ने कहा कि आयकर विभाग करदाताओं को सही कर रिटर्न दाखिल करने में मदद के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) या कापोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से 26एएस के रूप में मिलने वाली सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बजट के बाद एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा, हम लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि करदाता स्वेच्छा से कर कानूनों का पालन करें और ईमानदार करदाताओं को ऐसी सभी सुविधाएँ मिलें, जिसके वे हकदार हैं और इसके साथ ही जो लोग गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाएगा।'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2021-22 के बजट भाषण में कहा था कि छोटे करदाताओं के मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विवाद समाधान समिति (डीआरसी) की स्थापना की जाएगी, जहाँ 50 लाख रुपए तक कर योग्य आय और 10 लाख रुपए तक विवादित आय वाले करदाता अपील कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि डीआरसी की स्थापना के पीछे सोच यह है कि निपटान आयोग वास्तव में छोटे करदाताओं की जरूरतों को पूरा नहीं करता था। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र बनाने की कोशिश की है। इसकी कई शाखाएँ होंगी और यह छोटे करदाताओं की जरूरतों को पूरा करेगा। मुझे लगता है कि इससे उन्हें कठोर अपीलीय प्रक्रिया से गुजरे बिना अपने कर मामलों को निपटाने का मौका मिलेगा।' **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 4.2.2021)**

पर्यटन निगम के सभी होटल चलेंगे लीज पर

बिहार पर्यटन विकास निगम अपने और नौ होटलों को घाटे से उबारने के लिए उन्हें लीज पर देने जा रहा है। राज्यभर में निगम के 26 होटल हैं, जो मुनाफे में नहीं हैं। इनमें कुछ होटल नो प्रॉफिट–नो लॉस पर तो कुछ घाटे में चल रहे हैं। निगम 17 होटलों को पहले से लीज पर दे चुका है। अब शेष नौ में आठ होटलों को भी लीज पर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.2.2021)**

उर्वरक खपत
(कृषि योग्य भूमि पर किलोग्राम/हेक्टेयर)

भारत	165.8	अमेरिका	138.6
विश्व	140.6	मेक्सिको	114.0
न्यूजीलैंड	1777.2	नेपाल	74.1
मलेशिया	1723.4	ऑस्ट्रेलिया	68.1
इस्राइल	280.7	रूप	18.5
जापान	242.2	भूटान	13.3
फ्रांस	163.1	अफगानिस्तान	12.2
पाकिस्तान	144.3		

(साभार : प्रभात खबर, 8.2.2021)

खाद–बीज डीलरों को माप–तौल का भी अब लाइसेंस लेना होगा

राज्य में अब खाद, बीज व कीटनाशी के डीलरों को माप–तौल का भी लाइसेंस लेना होगा। जैविक खाद की व्यावसायिक इकाई लगाने वाले और इसके व्यापार से जुड़े डीलरों के लिए भी यह जरूरी होगा। नया लाइसेंस के लिए आवेदन करने के पहले यह व्यवस्था कर लेनी होगी। साथ ही, पुराने डीलरों को भी अब तीन महीने के भीतर माप–तौल का लाइसेंस ले लेना होगा।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 8.2.2021)

बिहार की स्मार्ट प्रीपेड मीटर योजना देश में लागू होगी

देश को बिजली में कई मॉडल दे चुके बिहार के प्रीपेड मीटर को भी अब देश अपनाएगा। बिहार ही इकलौता राज्य हैं जहाँ स्मार्ट प्री–पेड मीटर लगाए जा रहे हैं। बाकी राज्यों में पोस्टपेड स्मार्ट मीटर ही लगाए जा रहे हैं। आम बजट–2021 पेश करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार के प्रीपेड मीटर को देशभर में अपनाने की घोषणा की। बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की शुरूआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर हुआ।

बिहार ने देश को दिया : • हर घर बिजली योजना सौभाग्य योजना से देश भर में लागू • अनुदानरहित बिजली दर को अब अपना रहे दूसरे राज्य • हर घर बिजली कनेक्शन पहुँचाने के लिए बिजली एप को अपनाया • स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के मोबाइल एप को भी अपना चुका है देश

निर्णय क्यों : बिहार में अभी एक करोड़ 62 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ता हैं। इसमें 92 फीसदी घरेलू उपभोक्ता हैं। यानी व्यवसायिक और उद्योग श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या मात्र आठ फीसदी है। ऐसे में जब आम लोग बिजली का बिल समय पर जमा नहीं करते हैं तो कंपनी नुकसान में चली जाती है जिससे सरकार को हर साल हजारों करोड़ अनुदान के रूप में देना पड़ता है। प्रीपेड मीटर से कंपनी को हो रहा नुकसान समाप्त हो सकता है।

"प्री–पेड स्मार्ट मीटर लगाने की बिहार की योजना अब पूरे देश में लागू होगी। इस काम को केन्द्र सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।"

– नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार

(साभार : हिन्दुस्तान, 2.2.2021)

एक देश, एक बैंक–लोकपाल होगा

रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के निष्कर्षों की जानकारी देते हुए कहा, विवादों को सुलटाने की वैकल्पिक व्यवस्था को सरल बनाने तथा विनियमित निकायों के ग्राहकों के प्रति इसे अधिक जवाबदेह बनाने के लिए तीनों बैंक–लोकप्रहरी व्यवस्थाओं का विलय कर एक देश, एक बैंक–लोकप्रहरी की अवधारणा को अमल में लाने का निर्णय लिया गया है। आरबीआई ने विनियमित निकायों के द्वारा संतोषजनक समाधान नहीं निकाले जाने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करने के लिए शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) पोर्टल की शुरुआत की थी।

सीटीएस पूरी तरह लागू : रिजर्व बैंक कहा कि सभी शेष 18,000 शाखाएँ, जो केन्द्रीकृत समाशोधन प्रणाली चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) के तहत नहीं हैं, उन्हें सितम्बर तक सीटीएस के दायरे में लाया जाएगा।

भुगतान एप भी दायर में आएँगे : रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि इस कदम का लक्ष्य एक केन्द्रीयकृत संदर्भ प्रदान कर एकीकृत योजना के तहत बैंकों, एनबीएफसी तथा प्रीपेड भुगतान समाधान मुहैया कराने वाली गैर–बैंकिंग कंपनियों के ग्राहकों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल मंच प्रदान करना है। आरबीआई गवर्नर दास ने कहा कि रिजर्व बैंक ई–इंटीग्रेटेड बैंक लोकप्रहरी योजना को जून 2021 से शुरू करना चाह रहा है।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 6.2.2021)

घर खरीदारों को 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने किफायती घर खरीदने पर मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया है। इसके लिए घर की कीमत अधिकतम 45 लाख रुपये होना चाहिए। साथ ही इस लाभ को पाने के लिए आपके पास पहले से कोई दूसरी प्रोपर्टी नहीं होनी चाहिए। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 4.2.2021)**

Statement about ownership and other particulars about newspaper of the Bihar Chamber of Commerce & Industries monthly Bulletin to be published in the first issue every year after last day of February.

Form - IV
(See Rule -8)

1.	Place of Publication	Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800 001
2.	Periodicity of its publication	Monthly
3.	Printer's Name Whether Citizen of India? (If foreigner, state the Country of origin) Address	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
4.	Publisher's Name Whether Citizen of India? (if foreigner, State the Country of Origin) Addrss	A. K. Dubey Indian Deputy Secretary Bihar Chamber of Commerce & Industries, Khem Chand Chaudhary Marg, Patna-800001
5.	Editor's Name Whether Citizen of India? (If Foreigner, State the Country of Origin) Address	Shri Amit Mukherji Indian M/s Standard Industries 35, New Market Patna - 800 001
6.	Name and Address of Individual who own the newspaper and partners of Share-holders	Bihar Chamber of Commerce & Industries Khem Chand Chaudhary Marg Patna-800 001

I, A. K. Dubey, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

A. K. Dubey
Publisher

PT.GPO/R-10/NP-15/2017-19 R. N. 4211/62

माननीय उद्योग मंत्री से मिला चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल

माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन को पुष्पगुच्छ देकर अभिनन्दन करते चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। उनकी दाँयीं और चैम्बर उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर एवं श्री रामा शंकर प्रसाद

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के नेतृत्व में चैम्बर का एक प्रतिनिधिमंडल दिनांक 10 फरवरी 2021 को माननीय उद्योग मंत्री सैय्यद शाहनवाज हुसैन से उनके कार्यालय कक्ष में मिलकर बधाई दी एवं उनका अभिनन्दन किया।

चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने माननीय उद्योग मंत्री के साथ राज्य के औद्योगिक एवं आर्थिक उत्थान पर विचार-विमर्श किया तथा चैम्बर की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

श्री अग्रवाल ने बताया कि सैय्यद शाहनवाज हुसैन द्वारा पूर्व में किये गये कार्यों को देखकर बिहार के उद्यमियों में एक नई उर्जा का संचार हुआ है और आशान्वित हैं कि राज्य में औद्योगीकरण की गति में अवश्य तेजी आएगी। उन्होंने आगे कहा कि गत कुछ माह से सरकार की ओर से राज्य में अधिकाधिक रोजगार का अवसर पैदा करने की जो बात चल रही है वह राज्य में नये उद्योगों की स्थापना से ही संभव हो सकेगा।

चैम्बर अध्यक्ष ने बताया कि राज्य में अधिकाधिक रोजगार सृजन के लिए यह आवश्यक है कि राज्य में स्टील, ऑटोमोबाइल, अल्युमिनियम, पेट्रोलियम जैसे वृहत उद्योगों की स्थापना हो क्योंकि बड़े उद्योग लगेंगे तो स्वभाविक है कि साथ-साथ कई सहयोगी इकाइयाँ भी स्थापित होंगी जिससे राज्य का आर्थिक विकास होगा एवं लोगों को रोजगार भी मिलेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि माननीय उद्योग मंत्री ने चैम्बर प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया है कि जल्द ही राज्य के उद्यमियों से सीधी वार्ता का आयोजन किया जाएगा। साथ ही चैम्बर प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर चैम्बर पधारने का भी आश्वासन दिया है।

प्रतिनिधिमंडल में चैम्बर अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल के अतिरिक्त उपाध्यक्ष श्री एन. के. ठाकुर, कोषाध्यक्ष श्री विशाल टेकरीवाल, वरीय सदस्य श्री रामा शंकर प्रसाद एवं श्री अलोक पोद्दार शामिल थे।

नए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दिए तीन मंत्र... इनवेस्टमेंट, इंडस्ट्रीज और इम्प्लायमेंट इन बिहार

उद्योग पर लोगों की राय लेने के लिए विभाग की वेबसाइट पर होगा विंडो

राज्य में उद्योग विभाग का जिम्मा शाहनवाज हुसैन जैसे कद के नेता को मिलना बताता है कि नई सरकार का यह अब फोकस एरिया है। चुनौती बड़ी है। विभाग का पदभार ग्रहण करते ही एक्शन में आए शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार में उद्योग को लेकर श्रीबाबू ने जो सपना देखा था, उसे पूरा करना मेरी प्राथमिकता होगी। **सपने को धरातल पर उतारने के लिए उन्होंने तीन मंत्र भी गिनाए .... इनवेंस्ट इन बिहार, इण्डस्ट्रीज इन बिहार और इम्प्लायमेंट इन बिहार।**

उन्होंने कहा– इसी सिद्धांत पर काम करेंगे और जिस भरोसे के साथ केन्द्रीय नेतृत्व ने बिहार भेजा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उस पर खरा उतरने की हर संभव कोशिश रहेगी।

निवेशकों को बुलाने की हर संभव कोशिश : उद्योग मंत्री ने कहा कि देश के बड़े औद्योगिक शहरों के अलावा विदेशों में जाऊँगा और वहाँ के बड़े निवेशकों से बिहार में निवेश करने का आग्रह करुंगा।

राज्य में उद्योग धंधे के लिए माकूल माहौल : राज्य में उद्योग धंधे के विकास के लिए माकूल माहौल तैयार है। बिहार में बीते 15 साल में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित हो चुका है। यहाँ पर्याप्त बिजली है, पानी है, हुनरमंद हाथ हैं, संसाधन है... लिहाजा अब बिहार को इण्डस्ट्रियल टेकऑफ कराने की जरूरत है। ऐसा होते ही बिहार के लोगों को रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। राज्य में रोजगार बढ़ाना एनडीए सरकार की टॉप प्राथमिकता है और यह गुरुतर दायित्व मेरे कंधों पर है।

(साभार : दैनिक भास्कर, 11.2.2021)

EDITORIAL BOARD

Editor
AMIT MUKHERJI
Secretary General

Convenor
RAMCHANDRA PRASAD
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 2677605, 2677635 • Fax No. : 0612-2677505
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296